



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 1 दिसम्बर, 2011/10 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 अक्टूबर, 2011

संख्या टी.एस.एम-एफ (6)-3/2009-II.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (2) के खण्ड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी.एस.एम-एफ(5)-9/2000 तारीख 10-6-2005 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8-7-2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम, 2005 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करती हैं और जिन्हें इसमें सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए राजपत्र हिमाचल प्रदेश में एतद्वारा प्रकाशित किया जा रहा है ;

कोई हितबद्ध व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/सुझाव देना चाहता हो, तो वह उसे (उन्हें) इन प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर निदेशक, (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)/प्रधान सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा ;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (आक्षेपों) या सुझाव (सुझावों) पर, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा इन प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2011 है।

2. **नियम 2 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम, 2005 के नियम 2 के उपनियम (1) में, खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(झ) “सीजन” से, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, पन्द्रह जुलाई से पन्द्रह सितम्बर की अवधि, जिसके दौरान कोई भी रीवर राफ्टिंग प्रचालन अनुज्ञात नहीं होगा, को छोड़कर सम्पूर्ण वर्ष अभिप्रेत है;

परन्तु जिला लाहौल एवं स्पीति में एक जून से इक्तीस अक्टूबर के दौरान राफ्टिंग प्रचालन किया जा सकेगा यदि मौसम परिस्थितियां ऐसा करने दें।

आदेश द्वारा,
मनीषा नन्दा,
प्रधान सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

[Authoritative English text of this Department notification number Tsm-F(6)-2/2009-II dated 14.10.2011 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14 th October, 2011

No.Tsm-F(6)-2/2009-II.—In exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of subsection (2) of Section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005 published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 8-7-2005 vide this department Notification No.Tsm-F(5)-9/2000 dated 10-6-2005 and the same are hereby published in the Rajpatra of Himachal Pradesh for the information of the persons likely to be affected thereby;

Any interested person who has any objections(s) / suggestion(s) with regard to the proposed amendments, may send the same to the Director (Tourism & Civil Aviation) / Pr.Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The Objection(s) or suggestion(s) if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government before finalizing the draft rules, namely :-

1. **Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh River Rafting (Amendment) Rules, 2011.

2. **Amendment of rule 2.**— In sub rule (1) of rule 2 of the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005 for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

- “(i) “season” for the purposes of these rules means whole of the year excluding the period from 15th July to 15th September during which no river rafting operation shall be permitted.

Provided that rafting operation may be permitted in District Lahaul and Spiti during 1st June to 31st October, if the weather conditions permit to do so.”

By order,
MANISHA NANDA,
Pr. Secretary(Tourism & Civil Aviation).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2011

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 35 / 2008.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में हरनोडा पंचायत घर से कसोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मण्डी क्षेत्र) मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(बीघा10 में)
बिलासपुर	सदर	कसोल	427 / 1	7-18
			431 / 1	7-19
			437 / 1 / 2	3-9
			439 / 1	10-10
			435 / 1	5-18

436 / 1	3-18
2	9-3
3	9-2
577 / 5	9-11
6	4-3
7	3-10
578 / 8	4-6
583 / 11	0-17
585 / 12	1-12
कुल किता 14	81-16

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर, 2011

संख्या पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 22/2011.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव चमयौण, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश मे हरनोडा पंचायत घर से कसोल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (मण्डी क्षेत्र) मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(बीघा0 में)
बिलासपुर	सदर	चमयौण	205 / 56 / 2 / 1	0-5
कुल किता-1				0-5

वित्त विभाग

कोष लेखा एवं लॉटरी

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2011

संख्या 3-1/75 फिन: (टी0एण्डए0)-III.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग में मान्यता प्राप्त अधीनस्थ लेखा सेवा प्रशिक्षण संस्थान (हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान “हिपा”) और अधीनस्थ लेखा सेवा, (सामान्य शाखा) भाग-I और भाग-II परीक्षा में प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक चयन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा, (सामान्य शाखा) प्रशिक्षण और परीक्षा नियम, 2011 है ।

2. ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—1. ये नियम हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों जो नियम 4(क) और (ख) में यथा-अधि कथित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, लागू होंगे ।

2. ये नियम हिमाचल प्रदेश में निगमों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों के उन कर्मचारियों को, जो नियम 4(क) और (ख) में यथा अधि-कथित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, लागू होंगे ।

3. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) “आयोग” से जहां कहीं प्रयुक्त हुआ है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग अभिप्रेत हैं,
- (ख) “विभाग” से हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्त (कोष, लेखा एवं लॉटरी) विभाग अभिप्रेत है ,
- (ग) “निदेशक” से निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग अभिप्रेत है ,
- (घ) “कर्मचारियों” से प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा के साथ-साथ अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I और II परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारी और हिमाचल प्रदेश सरकार तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारी तथा निगमों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों के कर्मचारी भी अभिप्रेत हैं,
- (ङ) “सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ।
- (च) “संक्षेपाक्षर” एच0आई0पी0ए0 (हिपा) से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला अभिप्रेत है, और
- (छ) “संक्षेपाक्षर” एस0ए0एस0 (ओ0बी0) से हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) अभिप्रेत है ।

4. **प्रतियोगी अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता.**—(क) (1) इन नियमों में विदित अन्य शर्तों के अध्यधीन, कर्मचारियों के निम्नलिखित प्रवर्ग, आयोग द्वारा, अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के प्रारम्भिक चयन हेतु, संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे ।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार और निगमों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों/स्थानीय निकायों आदि के अधीन पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने वाले समस्त कर्मचारी, जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि रखते हों ।

(ख) प्रतियोगी अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 (ब्यालीस) वर्ष होगी ।

टिप्पण.—प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें कर्मचारियों से आवेदन आमन्त्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है।

(ग) प्रतियोगी अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यार्थी (कर्मचारी) विशेष अवकाश के हकदार नहीं होंगे, परन्तु जिसके लिए उन्हें अपने नियोजक से छुट्टी लेनी अपेक्षित होगी।

(घ) कर्मचारियों को प्रतियोगी लेखा सेवा (सामान्य शाखा) प्रवेश परीक्षा में बैठने के खर्च को स्वयं वहन करना होगा।

(ङ.) अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग—I और II परीक्षा के लिए प्रशिक्षण ले रहे चयनित प्रभिक्षु अभ्यार्थियों को, पचास हजार रुपये की रकम का, इतनी ही रकम की दो प्रतिभूतियों सहित, निदेशक, हिमाचल प्रदेश को उनके प्रवेश से पूर्व अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग—I और II प्रशिक्षण/परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और अर्हित करने के पश्चात्, कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा करने का, बंधपत्र निष्पादित करना अपेक्षित होगा।

5. प्रवेश परीक्षा के लिए विषय और पाठ्यक्रम.—प्रवेश परीक्षा के लिए विषय और पाठ्यक्रम निम्नलिखित होगा :

पेपर— I	अंग्रेजी और हिन्दी	सार लेखन, पत्रलेखन, टिप्पण और प्रारूपण तथा अभ्यार्थियों की शुद्ध अंग्रेजी/हिन्दी लिखने की योग्यता को जांचने के अन्य सामान्य प्रश्न/अंग्रेजी/हिन्दी भाग के 75 अंक होंगे।
पेपर— II	बहुशीर्ष लेखे	प्रश्न वेतन नियतन, पेंशन, यात्रा भत्ता, अवकाश यात्रा सुविधा, छुट्टी और सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित नियमों के होंगे।
पेपर— III	हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009.

टिप्पण—1. अंग्रेजी के पेपर का स्तर, किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय की उपाधि की परीक्षा के समतुल्य होगा और हिन्दी पेपर का स्तर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्कूल शिक्षा बोर्ड की दस जमा दो की परीक्षा के बराबर या इसके समतुल्य होगा।

टिप्पण—2. प्रत्येक पेपर 150 अंकों का होगा (पेपर—I अंग्रेजी 75 अंक, हिन्दी 75 अंक) और उसकी अवधि तीन घण्टे होगी।

टिप्पण—3 परीक्षा का माध्यम, अंग्रेजी होगा, सिवाय पेपर—I के, जिसके लिए परीक्षा का माध्यम भाग—अनुसार अंग्रेजी और हिन्दी दोनों होंगे।

6. प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की संख्या.—(क) (1) किसी भी कर्मचारी को, प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए तीन से अधिक अवसर अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(2) जो अभ्यार्थी प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् आयोजित की गई अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में अन्तिम रूप से असफल घोषित किए गए हैं, वे पुनः प्रवेश परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

7. प्रशिक्षण के लिए अभ्यार्थियों का चयन.—(क) सरकार अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) प्रवेश परीक्षा की खुली प्रतियोगिता संचालित करने के लिए, वर्ष के 31 मार्च तक की संभाव्य रिक्तियों, जिसमें सरकार ने संभाव्य रिक्तियों को भरने का विनिश्चय किया है, के बारे में हिमाचल लोक सेवा आयोग को अध्यक्षता भेजेगी। आयोग उस वर्ष के मई/जून मास में, जब तक आयोग परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए अन्यथा विनिश्चय नहीं करता है, प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उसके द्वारा विहित रीति में पूर्वोत्तर परीक्षा, संचालित करेगा। सरकार अध्यक्षता को वित्त विभाग में भेजते समय, आगामी दो वर्षों के दौरान भरी जाने वाली अवधारित रिक्तियों की संख्या, विभिन्न प्रवर्गों आदि के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, की बाबत ब्योरे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करेगी।

(ख) प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों का चयन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े प्रवर्ग, अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी आदेशों के अध्वधीन होगा ।

(ग) (1) प्रत्येक पेपर में न्यूनतम पास अंक चालीस प्रतिशत और संकलित पेपरों में पैतालिस प्रतिशत होंगे, किन्तु आरक्षित प्रवर्ग के लिए प्रतिशत कमशः पांच प्रतिशत कम होगी ।

(2) अन्तिम चयन, आरक्षित प्रवर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए सर्वथा पाठ्यक्रम के गुणागुण के क्रम में किया जाएगा ।

(3) आयोग हिपा में अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग-I और II परीक्षा के प्रशिक्षण के लिए भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन, सम्बद्ध अभ्यर्थियों के साथ-साथ सम्बद्ध अभ्यर्थियों के सम्बद्ध विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों, निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, सरकार और वित्त विभाग को सूचित करेगा ।

8. प्रशिक्षण.—(क) निदेशक, हिपा प्रशिक्षण हेतु चयनित सम्बद्ध अभ्यर्थियों को, अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I और II (सामान्य शाखा) परीक्षा के लिए प्रशिक्षण के प्रारम्भ हेतु नियत तारीख को, प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने हेतु सूचित करेगा ।

(ख) यदि कोई प्रशिक्षु अभ्यर्थी प्रशिक्षण के आरम्भ के लिए नियत तारीख तक निदेशक, हिपा को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करने में असफल रहता है, तो निदेशक, हिपा, ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को प्रशिक्षु के लिखित अनुरोध पर माफ कर सकेगा यदि ऐसी अनुपस्थिति के लिए दिए गए कारण आवेदक के नियन्त्रण से परे थे और निदेशक, हिपा की यह राय है कि आवेदक के लिए व्यतीत अवधि की कमी को पूरा करना सम्भव है ।

(ग) अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I और II के प्रत्येक भाग के लिए प्रशिक्षण की अवधि पांच मास होगी ।

(घ) अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I और II को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात, वित्त विभाग में प्रशिक्षु अभ्यर्थियों की नियुक्ति, उसके पक्ष में, पैतृक कार्यालय/नियुक्त व्यक्ति के विभाग द्वारा सतर्कता विभाग से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के अध्वधीन होगी ।

(ङ.) अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I और II के प्रशिक्षण की अवधि को, कर्तव्य (डियूटी) अवधि ही समझा जाएगा :

परन्तु नियम 9 के उप नियम क (VI) (छूट खण्ड) के अनुसार अधीनस्थ लेखा सेवा भाग- II के लिए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए अनुज्ञात किए गए अभ्यर्थियों की बाबत, प्रशिक्षण की अवधि को केवल कर्तव्य (डियूटी) पर समझा जाएगा यदि वे देय छुट्टी की अवधि के रूप में पश्चातवर्ती सत्र में अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-1 की परीक्षा अर्हित कर लेते हैं तथा वे किसी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे ।

9. परीक्षा और परिणाम.—(क) हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में अधीनस्थ लेखा सेवा के लिए प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों के लिए अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग-I और II परीक्षा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न प्रकार से संचालित की जाएगी:

- I. अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग-I और II परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, संलग्न उपबन्ध के अनुसार होगा । (A & AI)
- II. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान से अधीनस्थ लेखा सेवा (सामान्य शाखा) भाग-I और II के प्रशिक्षण के पूर्ण होने की तारीख की बाबत सूचना प्राप्त होने पर, प्रशिक्षण के पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात की तारीख को परीक्षा

संचालित करेगा। निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ऐसी सूचना को प्रशिक्षण के पूर्ण होने से कम से कम डेढ़ मास पूर्व भेजेगा।

- III. अभ्यर्थी को परीक्षा के किसी भी भाग में तीन से अधिक बार भाग लेना अनुज्ञात नहीं होगा।
- IV. परीक्षा के पास करने के आशय से, अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर में पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। जहां पेपर में दो भाग होंगे, वहां दोनों भागों में प्राप्त किए गए अंकों को इकट्ठे संगणित किया जाएगा।
- V. अभ्यर्थी जिसने किसी पेपर (पेपरों) में पच्चपन प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, परन्तु परीक्षा में पूर्णतः अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उससे परीक्षा में उस पेपर (पेपरों) में बैठने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- VI. कोई अभ्यर्थी जब तक अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I की परीक्षा अर्हित नहीं कर लेता है, तब तक वह अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-II के प्रशिक्षण और परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा तथापि उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उपरोक्त पैरा (V) के अधीन कम से कम तीन (3) पेपरों में छूट अनुज्ञात की गई है, उन्हें अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-II के लिए प्रशिक्षण लेने और अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-II परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उनका अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-II का परिणाम तब तक घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक वे अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I परीक्षा अर्हित नहीं कर लेते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-I परीक्षा को तीन अवसर प्राप्त करने के बावजूद भी अर्हित करने में असफल रहता है, तो उसका अधीनस्थ लेखा सेवा भाग-II का परिणाम स्वतः ही रद्द हो जाएगा।
- VII. अभ्यर्थी से, उन पेपरों की परीक्षा में, जिनमें ऐसी पुस्तकों की सहायता अनुज्ञात है, अपनी पुस्तकें लानी अपेक्षित होंगी। उन पुस्तकों में कोई अप्रासंगिक विषय अन्तर्विष्ट नहीं होने चाहिए, किन्तु वे केवल सन्दर्भ की पुस्तकें होनी चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अनुचित तरीके अपनाने में लिप्त पाया जाता है और परीक्षा के दौरान कोई अनाधिकृत पुस्तक/सामग्री लाता है, तो वह कार्यवाही के लिए दायी होगा/होगी, तथा जो निम्न प्रकार से होगी:

(क) यदि, वह परीक्षा के लिए किसी प्रकार के अनुचित तरीकों को अपनाने का दोषी पाया जाता है/पाई जाती है, तो उसे प्रवेश के लिए निरर्हित किया जा सकेगा, या

(ख) यदि, वह उक्त परीक्षा की दो या अधिक परीक्षाओं में किसी प्रकार के अनुचित तरीके अपनाने का दोषी पाया जाता है/पाई जाती है, तो उसे सम्पूर्ण परीक्षा में प्रवेश के लिए निरर्हित किया जा सकेगा।

10. निरसन और व्यावृत्तियां।—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या:3-1/75-फिन (टी0एण्ड0ए0) तारीख 16 मई, 1985 द्वारा अधिसूचित दी रूलज फॉर इनिशियल सिलेक्शन ऑफ केण्डीडेटस फॉर अण्डरगोइंग ट्रेनिंग इन ए रिकांगनाइज्ड इन्सटीच्यूट एण्ड सर्वोडिनेट एकाउन्टस सर्विस (ओ0बी0) पार्ट-I एण्ड पार्ट-II का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
प्रधान सचिव (वित्त)।

[Authoritative English text of this Department notification No. 3-1/75-Fin(T&A)-III dated 15.11.2011 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

FINANCE DEPARTMENT
Treasuries, Accounts and Lotteries

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 15th November, 2011

No. 13-1/75-Fin(T&A)-III.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the following Rules for initial selection of candidates for undergoing training in a recognized SAS Training Institute(i.e Himachal Pradesh Institute of Public Administration “HIPA) and Subordinate Accounts Service (Ordinary Branch) Part-I & II Examination in the Department of Treasuries, Accounts & Lotteries, Himachal Pradesh, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules shall be called The Himachal Pradesh Subordinate Accounts Service (Ordinary Branch) Training and Examination Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Applicability.—(1) These rules shall be applicable to all employees of the State Government of Himachal Pradesh who fulfill the eligibility conditions as laid down in rule 4 (a) and (b).

(2) These rules shall also be applicable to the employees of the Corporations/ Boards/ Autonomous Bodies/ Local Bodies in Himachal Pradesh who fulfill the eligibility conditions as laid down in rule 4 (a) and (b).

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

- (a) The “Commission” wherever used means the Himachal Pradesh Public Service Commission;
- (b) The “Department” means the Finance (Treasuries, Accounts and Lotteries) Department of Himachal Pradesh Government;
- (c) The “Director” means the Director, Treasuries, Accounts and Lotteries, Himachal Pradesh;
- (d) “Employees” means the Employees appearing in the competitive examination for training as well as Subordinate Accounts Service Part I & II examination and working in the offices of the State Government of Himachal Pradesh and its subordinate offices and also the employees of the Corporations/Boards/ Autonomous Bodies/ Local Bodies;
- (e) “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (f) The abbreviation “HIPA” means the Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Shimla; and.

- (g) The abbreviation “SAS (OB)” means the Himachal Pradesh Subordinate Accounts Service (Ordinary Branch).

4. Eligibility for competitive SAS(OB) entrance examination.—(a) (i) Subject to other conditions prescribed in these rules, the following categories of employees shall be eligible to sit in a competitive examination to be conducted by the Commission for initial selection of candidates for SAS(OB) training;

(ii) All employees having 5 years service under the Government of Himachal Pradesh and the employees of the Corporations/Boards/Autonomous Bodies/Local Bodies etc., possessing a Bachelor's Degree or equivalent thereto from a recognized University.

(b) Maximum age limit for appearing in the competitive SAS (OB) Entrance Examination shall be **42 years**.

Note.—The age limit for appearing in the competitive Entrance Examination shall be reckoned as on 1st day of the year in which the advertisement for inviting applications from the employees is issued by the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The Candidates (Employees) appearing in the competitive SAS(OB) Entrance Examination shall not be entitled for special leave for which they shall require to take leave from their employers.

(d) The employees shall have to bear their own expenditure for appearing in the competitive SAS(OB) Entrance Examination.

(e) The selected trainee candidates for undergoing the training for SAS(OB) Part-I & II Examination shall be required to execute a bond for an amount of Rs. 50,000/- with two sureties of the like amount to the Director of HIPA to serve the Government of Himachal Pradesh for a period of at least 5 years after successfully completing and qualifying the SAS(OB) Part I & II training/ Examination before their admission. The Director, HIPA shall submit the aforesaid executed bond to the Director of Treasuries, Accounts and Lotteries for safe custody.

5. Subject and syllabus for the entrance examination.—The subjects and syllabus for the entrance examination shall be as under: -

Paper-I	English and Hindi	Précis, letter writing, noting and drafting and other general questions to test the candidate's ability to write correct English/ Hindi. English/Hindi portion will carry 75 marks each.
Paper-II	Omnibus Accounts.	Questions will be on Rules relating to Pay Fixation, Pension, T.A, LTC, Leave and GPF.
Paper-III	FRs, SRs, Himachal Pradesh Financial Rules, 2009	(a) Fundamental Rules and Supplementary Rules (excluding rules covered in Paper- II). (b) Himachal Pradesh Financial Rules, 2009.

Note 1.—Standard of English Paper will be similar to that of the Degree Examination of any recognized Indian University and standard of Hindi paper shall be similar to that of 10+2 examination or equivalent of recognized University or Board of School Education.

Note 2.—Each paper shall carry 150 marks (Paper-I English-75, Hindi-75) and will be of three hours duration.

Note 3.—The medium of examination shall be English except for Paper-I for which the medium of examination shall be both English and Hindi part-wise.

6. Number of chances for appearing in entrance examination.—(a) (i) No employee shall be allowed more than three chances to sit in the entrance examination.

(ii) The candidates who have finally been declared unsuccessful in SAS examination held after completion of training will not be eligible to sit in the entrance examination again.

7. Selection of candidates for training.— (a). The Government shall send a requisition to the Himachal Pradesh Public Service Commission for conducting the open competitive SAS(OB) Entrance Examination against the likely vacancies latest by 31st March of the year in which the Government decides to commence the training for filling of likely vacancies. The Commission shall conduct the aforesaid examination in the manner prescribed by it keeping in view the syllabus for the entrance Examination in the month of May/June of the same year unless the Commission decides otherwise depending upon the circumstances. The Government in the Finance Department while sending the requisition shall clearly furnish the details regarding number of vacancies determined to be filled in during the next two years, number of vacancies reserved for various categories, etc.

(b) The selection of candidates for training shall be subject to the orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Backward Classes, other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

(c) (i) The minimum pass marks shall be 40 % in each paper and 45% in aggregate, but for reserved category the percentage will respectively be 5% less.

(ii) The final selection shall be made strictly in order of merit, of course keeping in view the reservation of seats for reserved categories.

(iii) The Commission shall intimate the final selection of candidates for undergoing training for Part-I & II SAS(OB) Examination at HIPA to the concerned Heads of Departments/Appointing Authorities of the candidates concerned, the Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration and the Government in Finance Department as well as to the candidates concerned.

8. Training.—(a) The Director of HIPA shall intimate the candidates concerned selected for undergoing training, the scheduled date of commencement of training for Part-I and II SAS(OB) Examination to report for training.

(b) In case any trainee candidates fails to report for training to the Director, HIPA by the scheduled date of the commencement of training, the period of such absence may be condoned by the Director of HIPA on the written request of the trainee provided the reasons for such absence were beyond the control of the applicant and the Director, HIPA is of the opinion that it is possible for the applicant to make up for the lost period.

(c) The period of training for SAS(OB) Part-I & II shall be 5 months in each part.

(d) The appointment of the trainee candidate in the Finance Department after the successful completion of Part-I & II SAS(OB) Examination shall be subject to the obtaining of the Vigilance Clearance Certificate in his favour by the parent office/ Department of the appointee from the Vigilance Department.

(e) The period of training of SAS (OB) Part-I & II shall be treated as duty:

Provided that the period of training in respect of the candidates allowed to undergo training for SAS (OB)Part II in accordance with sub rule (a)(vi) of rule 9 (exemption clause), shall be treated as duty only if they qualify the SAS (OB) Part-I examination in the subsequent session as leave of the kind due and they shall not be entitled for any T.A/ D.A.

9. Examination and result.—(a) The SAS(OB) Part-I and II examination for the candidates undergoing training for SAS in Himachal Pradesh Institute of Public Administration Shimla shall be conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission as under:-

- (i) The syllabus for SAS (OB) Part-I & II examination shall be as per annexure enclosed.(A & AI)
- (ii) The Himachal Pradesh Public Service Commission shall, on receipt of information regarding the date of completion of training of SAS (Ordinary Branch) Part-I & II from the Director of HIPA, conduct the examination on a date immediately after the completion of training. The Director, HIPA will send such information at least 1-1/2months before the completion of the training.
- (iii) A candidate shall not be allowed to appear in either part of the examination more than three times.
- (iv) In order to pass the examination, a candidate must obtain 50% marks in each paper. Where there are two parts in a paper, marks obtained in both the parts shall be counted together.
- (v) A candidate who obtains 55% or more marks in any paper (s), but fails in the examination as a whole, shall not be required to appear in that paper (s) in the subsequent examination.
- (vi) Unless a candidate qualifies SAS(OB) Part-I examination, he shall not be eligible to be admitted for part-II SAS training and examination. However, candidates who are allowed exemption at least in 3 (three) papers under Para (v) above, shall be allowed to undergo training for SAS(OB) Part-II and to appear in SAS (OB)Part-II examination but their result of SAS(OB) Part-II shall not be declared till they qualify the SAS(OB) Part-I examination. In case a candidate fails to qualify SAS(OB) Part-I examination even after availing three chances, his result for SAS (OB)Part-II shall stand cancelled automatically.
- (vii) Candidate shall be required to bring their own books in examination in those papers in which the aid of such books is allowed. Those books shall not contain any extraneous matter but shall be bare reference books. In case a candidate is found to have indulged in unfair means and brings in any un-authorized book /material during the examination he/she shall be liable for action and the same shall be as under:-
 - (a) He /She may be disqualified if found guilty of adopting any kind of unfair means for the test, he/ she is appearing in, or
 - (b) He/She may be disqualified for the entire examination if found guilty of adopting any kind of unfair means in 2 tests or more of the said examination, he/she is appearing in.

10. Repeal and Savings.—(1) The rules for initial selection of candidates for undergoing training in a recognized Institute and Subordinate Accounts Service (OB) Part-I & Part-II examination notified vide this Department Notification No. 13-1/75-Fin (T&A) dated the 16th May, 1985 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done, or any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

ANNEXURE A-I

SYLLABUS FOR HIMACHAL PRADESH STATE S.A.S.(OB) PART-II EXAMINATION

Sr. No.	Paper	Time allowed	Max. Marks	Syllabus
1.	Paper-I General Financial Matters and Procedure.(With Books)	3 Hrs.	150	1. Himachal Financial Rules ,2009(See Note) 2. H.P. treasury Rules and Subsidiary Treasury Rules. 3. Account Code Vol. II
2.	Paper-II Financial Markets and Financial Services(Without Books)	3 Hrs.	100	1. Introduction to Indian Financial System. 2. Financial Markets. 3. Money Markets <ol style="list-style-type: none"> Reserve Bank of India: role as a Banker to Government Call Money Treasury Bills Commercial Papers(CP's) Certificate of Deposits(CDs) Commercial Bills. Repos. 4. Financial Institutions. <ol style="list-style-type: none"> Mutual Funds Non Banking Financial Companies. Term Lending Institutions (Dev. Fin. Institutions)
3	Paper-III Cost Accounting and Audit (Without Books)	3 Hrs	100	<u>Cost Accounting (60 Marks)</u> 1. Introduction to Cost Accounting. a) Objective and scope of cost accounting b) Cost Centers and cost units c) Elements of cost. 2. Cost ascertainment a) Material cost i). Procurement Procedures, store procedures and documentation in respect of receipts and issue of stock, stock verification. ii). Inventory Control-techniques of fixing of minimum, maximum and recorder levels, economic order quantity, ABC classification, stock taking. iii). Inventory accounting iv). Consumption-identification with products of cost centers, basis for consumption centers in financial accounts, monitoring of consumption. b) Employee Cost. i). Attendance and payroll procedures, over view of statutory requirements, overtime, idle time and incentives. ii). Labour turnover iii). Utilization of direct and indirect labour, charging of labour cost, identifying labour hours with work orders or batch or capital jobs. c) Direct Expenses Sub- contracting- control on material movements, identification with the main product or service. d) Overheads i). Functional analysis- factory, administration, selling, distribution, research and development. ii). Behavioral analysis – fixed, variable, semi variable. 3. Costing System i) Job Costing ii) Batch Costing iii) Contract iv) Process Costing <u>Auditing [40 marks]</u> 1 Auditing Concepts- Nature and limitations

				<p>of Auditing, basic principles governing an audit, Ethical principles and concept of Auditor's Independence.</p> <p>2 Auditing engagement – Audit planning, Audit programme, Control of quality of audit work, Delegation and supervision of audit work.</p> <p>3 Documentation – Audit working papers, Audit files: Permanent and current audit files, Ownership and custody of working papers.</p> <p>4 Internal Control - Elements of internal control, Review and documentation, Evaluation of internal control system . Internal control questionnaire, Internal control check list, Tests of Control. Application of concept of materiality and audit risk. Concept of Internal Audit.</p> <p>5 Internal Control and Computerized Environment:-Approaches to Auditing in Computerized Environment.</p> <p>6 Audit Sampling- Types of sampling, Test checking, Techniques of test checks.</p>
4	Paper-IV Advanced Commercial Accounts & Taxation (Without Books)	3 Hrs.	100	<p>Accounting (75 Marks)</p> <p>1. Method of Accounting-Mercantile (Accrual) or cash, with main emphasis on Mercantile (Accrual) Method of Accounting.</p> <p>2. Company Accounts: Preparation of financial statements-Profit and Loss Account, Balance sheet and Cash Flow statement.</p> <p>3. Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants</p>
5	Paper-V	2 ¼ Hrs.	100	<p>of India.</p> <p>Working knowledge of:-</p> <p>AS 1 : Disclosure of Accounting Policies</p> <p>AS 2 : Valuation of Inventories.</p> <p>AS 6 : Depreciation Accounting</p> <p>AS 9 : Revenue Recognition</p> <p>AS 10 : Accounting for Fixed Assets</p> <p>4. Accounting in Computerized Environment:- An overview of computerized accounting system-Salient features and significance, Concept of Grouping of accounts, Codification of accounts, Maintaining the hierarchy of ledger, Accounting packages and consideration for their selection. Generating Accounting Reports.</p> <p>Taxation: Income Tax (25 Marks)</p> <p>1. Important definitions in the Income Tax Act, 1961.</p> <p>2. Basis of charge:- Rates of taxes applicable for different types of assesses.</p> <p>3. Heads of Income: Salaries, Income from House Property, Profit and gains of business or profession, Capital Gains and Income from other sources.</p> <p>4. Income under the head salaries (Section 15 to 17)</p> <p>5. Relief when salary etc. is paid in arrears or in advance- Section 89.</p> <p>6. Provision for filing of return of income.</p> <p>1. Central P.W.D. Account Code(With special reference to preparation of Cash</p>

Local Rules and Public Works Account Code(Without Books)			Book, Contractor's Ledger, Preparation of Running Bills etc. and excluding the portion relating to Administrative matters) 2. Account Code Vol. III (Chapter I, II & III Sections 1,2,3,5 &6.) 3. CPWD Manual Vol. I.
--	--	--	---

Note-(i).The Himachal Pradesh Financial Rules,1971 volume I and II issued vide notification number 15/4(1971)R&EI Dated 10th May, 1971 and published in the Rajpata, Himachal Pradesh dated 15th July,1971 stand repealed. The Himachal Pradesh Budget Manual, 1971 also stands repealed.

(ii).Notwithstanding such repeal, any form(s), instruction(s), notification(s), office order(s), circular(s), letter(s), office memoranda, delegation(s),clarification(s), code(s), manual(s) or any other correspondence of any type issued or made under the rules so repealed, so far as they are not inconsistent with these rules, shall remain in force until superseded under these rules:

Provided that anything done or action taken under the provisions of rules so repealed, shall be deemed to have been validly done, taken under the corresponding provisions of these rules.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

अधिसूचना

शिमला-2, 30 नवम्बर. 2011

संख्या: एफ.डी.एस.ए.(3)-3/90-11.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले, विभाग) मंत्रालय द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण में तारीख 28.10.2011 को प्रकाशित का0आ02447(इ) तारीख 28.10.2011 के साथ पठित, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981से सलंगन अनुसूची-1 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) संशोधन आर्डर, 2011 है ।

2. **शडयूल-1 का संशोधन.**— हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकलज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981की अनुसूची-1 के भाग-ए (फूडग्रेन्स) के अधीन आर्टिकलज (वस्तुएँ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

भाग-ए (फूडग्रेन्स)

1. राइस (धान)
2. पैंडी (चावल)

आदेश द्वारा,
प्रेम कुमार,
 प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0 एवं उप0 मामले।

[Authoritative English text of this Department Notification No, FDS-A(3)-3/90-11, dated 30th Nov ,2011 as required under Article 348(3)of the Constitution of India].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 30th November, 2011

No. FDS-A(3)-3/90-II.—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing & Control) Order, 1981 read with S.O.2447(E), dated 28.10.2011 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department

of Consumer Affairs), Government of India and published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated 28.10.2011, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend Schedule-1 appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing & Control) Order, 1981, namely:—

1. Short title .—This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2011.

2. Amendmet of Schedule-1.— In the **Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing And Control) Order, 1981**, for **Schedule-1** for the articles under “**PART-**

“**A**” (**FOODGRAINS**)’ , the following shall be substituted, namely:-

“ **PART-A(FOODGRAINS)**”

1. “Rice”
2. “Paddy”

By order,
PREM KUMAR,
Principal Secretary (FCS&CA).

_____ S

FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st. November, 2011
1st December, 2011

No. FDS-B(2)-1/2005.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under Section 16(1) (a), 16(2) and 16(3) of the Consumer Protection Act, 1986 (as amended by Act No. 62 of 2002) and in consultation with the Hon’ble Chief Justice of the High Court of H.P., is pleased to appoint Mr. Justice Surjit Singh, Judge of H. P. High Court, as President of H. P. State Consumer Disputes Redressal Commission (to be known as State Commission) with effect from the date he assumes the charge as such on the terms and conditions stated below:—

1. Mr. Justice Surjit Singh, Judge of High Court shall be entitled to salary, allowances and other perquisites as were available to him as Judge of High Court (Last pay drawn minus pension). He shall also be entitled to the increase in Dearness allowance on account of revision from time to time subject to the condition that no I. R. and relief on pension shall be payable during the currency of tenure of his appointment as President of State Commission after his retirement as sitting Judge of High Court.
2. Mr. Justice Surjit Singh shall hold office of the President, State Commission for a term of 5 years or upto the age of 67 years, whichever is earlier and shall not be eligible for re-appointment.

By order,
RAJWANT SANDHU,
Chief Secretary.

